अनुमति के लिए, भेजा गया था। हालांकि विधेयक राष्ट्रपति द्वारा लौटाया नहीं गया है फिर भी, 12 मार्च, 1991 को लोक सभा में लाए गए और स्वीकार किए गए संशोधनों की विधिमान्यता के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। इनकी संवीक्षा की जा रही है।

(घ) ऐसे विधेयकों को लौटाए जाने के लिए न तो कोई समय-सीमा नियत की गई है और न नियत किए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव ही सरकार के विचाराधीन है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम

123. **डा० अबरा अहमद** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान परिवार नियोजन के राज्यवार लक्ष्य क्या निर्धारित किये गये थे तथा इस संबंध में इनकी उपलब्धियां क्या रहीं;

(ख) क्या यह सच है कि उपलब्धियों को दर्शाने वाले आंकड़ों में फर्जी आंकड़ों को शामिल किया गया था; और

(ग) सरकार बढ़ती हुई आबादी पर रोक लगाने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार नियोजन के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों को वर्षवार, राज्यवार और विधिवार रूप में दर्शाने वाले चार विवरण उपाबन्ध में दिए गए हैं। [देखिये परिशिष्ट 159, अनुपत्र सं० 7]

(ख) परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों के संबंध में उपलब्धियों के आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा सूचित किए गए निष्पादन आंकड़ों पर आधारित हैं। इस प्रकार के आंकड़ों की सत्यता को निश्चित करने के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा परिवार नियोजन स्वीकारकर्ताओं के संबंध में लगातार नमूना सत्यापन किया जाता है। इन एजेंसियों की उपलब्धियों को उपयुक्त उपचारी उपाय करने हेतु फिर से राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है ताकि कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।

(ग) देश में जनसंख्या वृद्धि को रोकने की नीति में शामिल है:—स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार/स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाना, व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम द्वारा "शिशु रक्षा दर को बढ़ाना, नए गर्भ निरोधक तरीके प्रदान करना, जनसंख्या शिक्षा को गहन बनाना, सामुदायिक सहयोग को बढ़ाना उन्नत संचार विधियों को अपनाना स्वैच्छिक सगठनों को आर्थिक सहयोग, निचले स्तर पर कार्मिकों के प्रशिक्षण और पुन: प्रशिक्षण के अधिक प्रयास, अधिक अंतर-क्षेत्रीय समन्वय स्थापित करना महिला शिक्षा और महिलाओं के स्तर में सुधार जैसे संबंधित विकास कार्यक्रमों के साथ सम्पर्क को सुदृढ़ बनाना और क्षेत्र-गहन तरीकों को अपनाना।

Export of Basmati Rice

123. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to export Basmati Rice during the current year;

(b) if so, what are the qualities thereof; and

(c) what are the names of the countries to which rice would be exported?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI SALMAN KHURSHEED): (a) to (c) The export of Basmati Rice is freely allowed under OGL. Government itself does not export basmati rice. There

are three grades of Basmati Rice which are exported, namely Special grade, A grade and B grade. Saudi Arabia, Bahrain, Oman, UAE, UK and USA are our main markets for basmati rice.

दसवीं लोक सभा के लिए चुनावों पर सरकार द्वारा किया गया व्यय

124. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं लोक सभा के लिये चुनावों पर केन्द्र सरकार द्वारा किये गये व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकारों द्वारा भी इस खर्च में कुछ अंशदान जाता है, यदि हां, तो विभिन्न राज्यों ने इसमें कितना-कितना अंशदान दिया; और

(ग) इस राशि में से सुरक्षा पर कितना खर्च किया गया?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) निर्वाचनों का संपूर्ण व्यय प्रारंभ में राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र जिनमें विधानमंडल हैं, वहन करते हैं तथा बाद में केन्द्रीय सरकार अपने भाग की प्रतिपूर्ति राज्यों को कर देती है। यह व्यय पुस्तकों में तीन उपशीर्षों में डाल दिया जाता है, जैसे, (i) निर्वाचन अधिकारी, (ii) मतदाता सूची की तैयारी और (iii) निर्वाचन का संचालन। पहले दो उपशीर्षों के अधीन हुआ व्यय केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें बराबर-बराबर वहन करती हैं (इसमें ऐसे संघ राज्यक्षेत्र, जिनमें विधानमंडल हैं, भी सम्मिलित हैं)। यदि निर्वाचन केवल लोकसभा के लिए होता है तो तीसरे उपशीर्ष के अधीन संपूर्ण व्यय केन्द्रीय सरकार वहन करती है और यदि राज्य विधान मंडल के लिए निर्वाचन होता है तो संपूर्ण व्यय राज्य सरकार वहन करती है। लोक सभा और राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन साथ-साथ होने की दशा में, तीसरे उपशीर्ष के अधीन हुआ व्यय भी केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें बराबर-बराबर बांट लेती हैं।

राज्य सरकारों के निर्वाचन व्यय के भाग की बाबत सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

Institutions for Imparting Vocational Training

125. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to set up more polytechnic institutions to prepare school leaving students to excel themselves in practical training in different kinds of activities such as electrical or mechanical works, carpentry, plumbing, etc.;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) if not, how Government propose to train people for self-employment to reduce unemployment?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) to (c) Government of India is assisting the State Governments to set up new polytechnics and to upgrade and modernise the existing ones where students are given broad-based training in various fields of Engineering and Technology relevant to the needs of industry and community.